

समान नागरिक संहिता

शर्मनाक हैं बच्चों के साथ पाशविकता की बढ़ती वारदातें!



गणेश कुमार अग्रवाल

उत्तराखण्ड सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है। जानकारी के अनुसार, इसमें सभी नागरिकों के कल्याण के लिए एक जैसे कानून का प्रताप है। हलात तथा तीन तलाक जैसी अमानवीय प्रथाओं को प्रतिवधि कर दिया गया है। सभी धर्मों की तलाक महिलाओं के लिए समान रूप से भाग की व्यवस्था की गई है। सभी लकड़ियों के विवाह की न्यूट्राम उम्र 18 वर्ष की दी गई है। तिवं-इन संवेदनों के कारण अक्सर विवाह और हिंसा की खबरें आती रहती हैं। इसमें निपटने के लिए उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बहुतांशु प्रथा को समाप्त करके सभी के लिए केवल एक विवाह का नियम प्रस्तावित है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की स्पष्ट व्यवस्था के बाबूजूद सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने से हिचकची रहीं। संविधान का अनुच्छेद 44 सबसे अधिक दुष्प्राप्ति के साथ बहुत अन्यथा हुआ है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है। इसमें सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह लिंग, क्षेत्र, भाषा की परवाह किए बौगर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए। जो मानवीय गरिमा का समान करे, उसे सुरक्षा बोध दे और सभ्य समाज के मानवों पर खाली भी उठाए। दुर्भाग्यवश अनुच्छेद 44 की इस परिवर्तन मांश को आगे बढ़ाने, उस पर संप्रयोग करने के बजाय उसे संप्रयोग करने के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात युक्त है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है।

देश भर में बच्चों से बलात्कार के मामले जिस तरीके से बढ़ने की खबरें समाने आ रही हैं, वह बेबद तिवंजनक है। बाल अधिकार से जुड़े एनजीओ ०८८१०८०५५५५% ने राष्ट्रीय अपाराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो (एनजीओ) के लिए एक जैसा कानून बनाना चाहता है। यह संतान व्यक्ति वाले किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी बंधु-परपरा को आगे बढ़ाना चाहता है या उससे उसको सुरक्षा बोध का एहसास होता है, तो उससे किसी पूजा-पद्धति की अवधानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून ने किसी समाज को सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाला होने के बाद उसे दर-बदर भटकने के बजाय युग्म-भर्ते की व्यवस्था की जाती है, तो इसमें उसका धर्म कहा से आड़े आता है? महिला-पुरुष के वैवाहिक संबंधों में यदि समाना सुनिश्चित की जाती है, तो इसमें किसी कानून ने किसी सभ्य समाज को शारीरिक नहीं, अपर्ण गर्व होना चाहिए। आजादी के बाद हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किया गए। तिवं-विवाह अधिनियम बहुविवाह पर अप्रतिवधि रूप देकर अलग बना चाहता है। यह दस्तूर आज भी कायम है। संविधान निर्माणीओं ने महसूस किया कि विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी पूजा-पद्धति से नहीं है, बल्कि इसका निकाला है कि बच्चों से बलात्कार के

मामले वर्ष 2016 से 2022 के बीच 96 फौसदी बढ़े हैं, जिनमें सभी प्रकार के %पैरिन्टेंटिव अस्याल्ट% शामिल हैं। 2016 में बच्चों से बलात्कार के मामले जहाँ 19765 थे, वहाँ 2022 में वह अंकड़ा बढ़कर 38911 हो गया। हालांकि यह मामले 2016 से ही बढ़ना शुरू नहीं हुए हैं बल्कि पिछले कई दशकों से यह मस्लिमिया चला आ रहा है।

10 साल में बच्चों के साथ 48,338 बलात्कार देश में जुर्म की बालात्कार के मामले जिस तरीके से बढ़ने की खबरें आगे बढ़ाने, उस पर संप्रयोग करने के बजाय उसे संप्रयोग करने के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात गई है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है। इसमें सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह लिंग, क्षेत्र, भाषा की परवाह किए बौगर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए। जो मानवीय गरिमा का समान करे, उसे सुरक्षा बोध दे और सभ्य समाज के मानवों पर खाली भी उठाए। दुर्भाग्यवश अनुच्छेद 44 की इस परिवर्तन मांश को आगे बढ़ाने, उस पर संप्रयोग करने के बजाय उसे संप्रयोग करने के लिए एक जैसा कानून बनाना चाहता है। यह दस्तूर आज भी कायम है। संविधान निर्माणीओं ने यह सुझाया कि विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी पूजा-पद्धति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध इसनियत से है। नि:संतान व्यक्ति वाले किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी बंधु-परपरा को आगे बढ़ाना चाहता है या उससे उसको सुरक्षा बोध का एहसास होता है, तो उससे किसी पूजा-पद्धति की अवधानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून ने किसी समाज को सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाला होने के बाद उसे दर-बदर भटकने के बजाय युग्म-भर्ते की व्यवस्था की जाती है, तो इसमें उसका धर्म कहा से आड़े आता है? महिला-पुरुष के वैवाहिक संबंधों में यदि समाना सुनिश्चित की जाती है, तो इसमें किसी भी सभ्य समाज को शारीरिक नहीं, अपर्ण गर्व होना चाहिए। आजादी के बाद हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किया गए। तिवं-विवाह अधिनियम बहुविवाह पर अप्रतिवधि रूप देकर अलग बना चाहता है। यह संतान व्यक्ति वाले किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी बंधु-परपरा को आगे बढ़ाना चाहता है या उससे उसको सुरक्षा बोध का एहसास होता है, तो उससे किसी पूजा-पद्धति की अवधानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून ने किसी समाज को सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाला होने के बाद उसे दर-बदर भटकने के बजाय युग्म-भर्ते की व्यवस्था की जाती है, तो इसमें उसका धर्म कहा से आड़े आता है? महिला-पुरुष के वैवाहिक संबंधों में यदि समाना सुनिश्चित की जाती है, तो इसमें किसी भी सभ्य समाज को शारीरिक नहीं, अपर्ण गर्व होना चाहिए। आजादी के बाद हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किया गया। यिनकी की संपत्ति वैटोरी को भी अधिकार देकर अपने परंपरा शुरू हुए हैं। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए अदालतें लगातार कोशिश करती रही हैं। मोहम्मद अहमद खान बनाना शाहबानों मामले (1985) में सुधीम कोट्ठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह खेद का विषय है कि अनुच्छेद 44 में तय राज्य की जिम्मेदारी अब अन्यीनी को व्यक्त करते हुए गढ़ रहे हैं। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार चर्चात होता है। इसके लिए एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकरण और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परं वोट बंध किसके की स्वीकृति सोच के कालए दुसरी जारी होने पर ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें बंध के मानवों के साथ लगातार च

सपा विधायक ने सदन में सरकार को घेरा

900 करोड़ के बिजली विभाग के घोटाले का मामला उठाया, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग की



जौनपुर। जौनपुर के मध्यस्थित विधायक डॉ. रामानी योनकर ने बजट सत्र में विधायक सभा में बुधवार को जिले के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। जनता की समस्याओं के लिए उन्होंने बिजली प्लांट के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री से भी सवाल किया। विधायक ने कहा कि जो परियोजनाओं के पूरा होने की टाइमलाइन दिया गया था। उस पर सरकार खीरी नहीं उतरी है।

300 यूनिट बिजली माफ करने की मांग की

विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की दलित, आदिवासी और गरीब जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के साथ पूर्वांचल विद्युत वितरण में गलत ढंग से

सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई

उन्होंने सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने भेटी लाइन बनवाई। गोमती रिवर फ्रेंट बनवाया, मेंदांत अस्पताल बनवाया, इंडियनीटी प्रोडक्शन यूनिट बनवाई, बच्चों को साक्षरता देने के लिए जगह-जगह लैपटॉप बटे, पुलिस हेडकॉर्ट बनवाया, लोकभवन बनवाया, एंबुलेंस दिया, डायल 100 दिया। जिसे आज 112 के नाम से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे काम कागज हैं और ये कोरा कागज लेकर रामराज्य की बात करते हैं। उन्होंने जनपद में बढ़ते अपराध का भी मुद्दा उठाया। कहा कि सरकार हर स्तर पर विफल रही है।

बिजली बिल बढ़ाकर 900 करोड़ के घोटाले का मामला संज्ञा में ले। उन्होंने

जनता पार्टी की सरकार को भगवान राम के आदर्शों पर चलने की नरीहत दी।

उन्होंने कहा कि भाजपा के जय श्री राम के गोरे में सब कुछ तो है, सृष्टि राम नहीं है। भगवान राम ने किसे दुःख उठाये।

इसके पूर्व बज सत्र में उन्होंने भारतीय

क्रुए में गिरकर युवक की मौत

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के थाना पचोखरा क्षेत्र में क्रुए में गिरकर युवक की मौत हो गई। बह खेत में पानी लगा रहा था। पुलिस ने बुधवार को मृतक के शव का पोटमार्ट कराया। पुलिस ने बताया कि गडी जारी निवासी हरिअम पुरु शिव सिंह मंगलवार की रात खेत में पानी लगा रहा था। इसके साथ ही आरोपी पर 40 हजार का जुमानी भी लगा रहा है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जब राम नारायण ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय मासम् बच्ची 17 जनवरी 2019 को गोरे में लगी रक्षीयता कराया।

। तभी आरोपी बिंदु गोड़ उर्मनंदकिशोर युवक को जबरदस्ती उड़ा ले गया और गांव के बाहर खेत में उसके साथ दुकर्म किया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी नंदकिशोर गोड़ के विद्युत चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्षी के तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र तथा दीलत यादव ने विधायिका विधायिका के शव का गांव रही है, जबकि उसकी भाजपा की बात करते हैं। वह चाहते तो अपने रिशेदारों और बड़े-समुदाय गयब वही है।

उन्होंने कहा कि जय श्री राम ने किसी तरफ नहीं दिया तो खेत पर काम कर रहे हैं अन्य लोगों ने उसकी तलाश की। बाद में पता चला कि वह क्रुए में गिर गया।

पुलिस मुठभेड़ में गिरफतार किया गया।

आप सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर में बयान दर्ज कराकर लौटे वापस

सुलतानपुर। दिल्ली के तिहाड़ जेल से आप आदामी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बुधवार को सुलतानपुर में एमपी-एमपीए कोर्ट में 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया।

आप नेता संजय सिंह के अधिवक्ता मदन रिंग ने बताया कि आप बुधवार को कोर्ट में थाएं जाएं तो अंतिम उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश के अन्तर्गत उत्तर के बायान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के लिए वापस भेज दिया।



50+
AGENTS

BUYING OR SELLING A PROPERTY?

LET'S WORK TOGETHER!

Buying or selling a property can be a stressful process if you don't have the right real estate agent. With 25 years of experience, you can rely on us to get you the best possible result.



CONTACT:

✉️ INFO@PROPRELUXURYREALESTATE.COM
📱 +91 9871577057
❤️ @PROPRELUXURYREALESTATE.COM